(c) Madras city has the highest rates for large and heavy industries. But in other areas of Madras State, the rates are not the highest. For large industries of 250 kW maximum demand, the lowest rates are in Kashmir area. The lowest rates for all the other types of large and heavy industries are in Mysore.

दिल्ली में बिजली शवदाह गृह

5694. **श्री राम गोपाल शालावाले:** क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में लोग बिजली शवदाह गृह में मृतकों को जलाने के विरुद्ध हैं तथा उस में बहुत कम मृतकों को जलाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत एक वर्ष में वहां कुल कितने मृतकों को जलाया गया ;

(घ) उस के कर्मचारियों पर कुल कितना वार्षिक धन खर्च हुआ है तथा इससे कुल कितनी वार्षिक आय हुई ; और

(ङ) शवदाह गृह के निर्माण पर कितना धन खर्च हुआ है ?

(स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति):

(क) यह सत्य है कि बिजली शवदाह गृह में बहुत कम मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है ।

(ख) इसके खास कारण क्या हैं यह बतलाना संभव नहीं है । संभवतया ऐसा लोगों की रूढ़िगत आदतों तथा धार्मिक पूर्वाग्रहों के कारण है ।

(ग) 1565 ।

(घ) शवदाह गृह के रख-रखाव पर प्रति वर्ष लगभग 1,60,000 रु० की रकम खर्च की जाती है तथा शवदाह-शुल्क के रूप में हर वर्ष लगभग 10,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है ।

(ङ) इस शवदाह गृह के निर्माण पर लगभग 3,30,000 रुपये खर्च हुए जिसमें भूमि-विकास, जलपूर्ति, बिजली सब-स्टेशन आदि का खर्च भी सम्मिलित है । केवल भवन की ही लागत लगभग 2,85,000 रुपये थी ।

REGISTERED MEDICAL PRACTITIONERS BILL

5695. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether there is resentment among the medical practitioners of Delhi over the proposed Registered Medical Practitioners Bill ; and

(b) if so, whether it is proposed to consider their demands before the legislation is brought forward ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) There were reports in the Press to that effect.

(b) The Delhi Administration and the Metropolitan Council have been advised to defer action in the matter. Government are aware of the views of the medical pratctitioners in the matter.

कुछ कम्पनियों द्वारा दिया गया आयकर

5696. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :